तीन हमलों का कानून। दोबारा बड़ा अपराध करने वाले अपराधी। दंडा पहल अधिनियम।

- तीन हमलों के कानून को संशोधित करके केवल उस समय उम्र कैद देता है, जब नए बड़े अपराध की दोषसिद्धि गंभीर या हिंसक हो।
- उन अपराधियों के लिए फिर से सजा देने को अधिकृत करता है जो इस समय उम्र कैद की सजा काट रहे हैं यदि तीसरे हमले की दोषसिद्धि गंभीर या हिंसक नहीं थी और जज निर्धारित करता है कि सजा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अनुचित जोखिम नहीं है।
- उम्र कैद दी सजा देना जारी रखता है यदि तीसरे हमले की दोषसिद्धि कुछ विशेष गैर-गंभीर, गैर-हिंसक यौन या नशीले पदार्थों के अपराध के लिए थी या इसमें बंदूक रखना शामिल था।
- गैर-गंभीर, गैर-हिंसक तीसरे हमले के अपराधियों के लिए उम्र कैद की सजा बनाए रखता है यदि पिछली दोषसिद्धि बलात्कार, हत्या, या बच्चे के यौन शोषण के लिए थी।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- जारी रहने के आधार पर जेल और पेट्रोल कार्यवाहियों से संबंधित राज्य की वार्षिक \$70 मिलियन की बचत, और आने वाले कुछ दशकों में—\$90 मिलियन तक की—और भी अधिक बचत। राज्य की भविष्य कार्यवाहियों पर निर्भर करते हुए इन अनुमानों में कई मिलियन कम या ज्यादा हो सकते हैं।
- कुछ विशेष अपराधियों को दोबारा सजा देने से संबंधित अदालत की कार्यवाहियों के लिए आने वाले कुछ वर्षों में राज्य और काउंटी के लिए एक बार होने वाले कुछ मिलियन डॉलरों के खर्चों।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

अपराधों की तीन श्रेणियां होती हैं: बड़े अपराध, छोटे अपराध, और उल्लंघन। बड़ा अपराध अत्यंत गंभीर किस्म का अपराध होता है, और इसमें दोषी ठहराये गए व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों के तहत राज्य जेल की सजा हो सकती है। बड़े अपराधों में दोषी ठहराये गए ऐसे व्यक्तियों जिन्हें राज्य जेल की सजा नहीं हुई उन्हें काउंटी जेल भेजा जाता है, काउंटी परिवीक्षा विभाग द्वारा समुदाय में उनकी निगरानी की जाती है, अथवा दोनो होता है।

मौजूदा कानून कुछ बड़े अपराधों को “हिंसक” या “गंभीर,” अथवा दोनों के रूप में वर्गीकृत करता है। इस समय बतौर हिंसक पारिभाषित बड़े अपराधों के उदाहरणों में हत्या, डकैती, और बलात्कार शामिल हैं। जबकि तकरीबन सभी हिंसक बड़े अपराध गंभीर भी माने जाते हैं, अन्य बड़े अपराध केवल गंभीर माने जाते हैं, जैसे डकैती की मंशा से हमला करना। ऐसे बड़े अपराधों जिन्हें हिंसक या गंभीर वर्गीकृत नहीं किया गया है, में बड़ी चोरी (जिसमें आग्नेयास्त्र शामिल नहीं हो) और किसी नियंत्रित वस्तु को रखना शामिल है।

मई 2012 में कैलिफोर्निया जेल व्यवस्था में 137,000 कैदी थे। 2012-13 में राज्य की जेल व्यवस्था के लिए बजट लगभग \$9 बिलियन था।

तीन हमलों की सजा। प्रस्ताव 184 (आमूमन “तीन हमलों” के कानून के तौर पर संदर्भित किया जाता है) 1994 में मतदाताओं द्वारा अंगीकृत किया गया था। यह कुछ विशेष दोबारा अपराध करने वालों को लम्बी अवधि की जेल की सजा लगाता है। विशेष तौर पर, कानून यह व्यवस्था देता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी बड़े अपराध में दोषी ठहराया गया हो और जो पहले भी एक या अधिक हिंसक या गंभीर बड़े अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका हो उसे निम्नलिखित तरीके से राज्य जेल की सजा होगी:

- **दूसरे हमले का अपराध।** यदि किसी व्यक्ति को पहले एक गंभीर या हिंसक अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है, तो किसी नये बड़े अपराध (केवल गंभीर या हिंसक अपराध नहीं) की सजा की अवधि **दोगुनी** होती है अन्यथा कानून के तहत नयी दोषसिद्धि की जरूरत पड़ती है। अदालतों द्वारा इस प्रावधान के तहत सजा पाए अपराधियों को “सेकंड स्ट्राइकर्स” कहा जाता है। मार्च 2012 तक लगभग 33,000 कैदी सेकंड स्ट्राइकर्स थे।

- **तीसरे हमले का अपराध।** यदि व्यक्ति को पहले से ही दो या इससे अधिक अपराध में दोषी ठहराया गया हो, तो किसी तीसरे अपराध (केवल गंभीर और हिंसक अपराध ही नहीं) की सजा उम्रकैद है जिसमें 25 साल के बाद ही पेरोल संभव है। इस प्रावधान के तहत दोषी ठहराये गए अपराधियों को “थर्ड स्ट्राइकर्स” कहा जाता है। मार्च 2012 तक लगभग 9,000 कैदी थर्ड स्ट्राइकर्स थे।

जब कानून को ऊपर वर्णित सजाओं की जरूरत होती है, कुछ मामलों में अदालत सजा सुनाने के दौरान पहले के बड़े अपराधों पर विचार नहीं करने का चुनाव कर सकती है। ऐसा होने पर, किसी अपराधी जिसे बतौर सेकंड या थर्ड स्ट्राइकर सजा हो सकती थी, को तीन हमलों के कानून के तहत जरूरी अवधि से कम की सजा होगी।

जेल रिहाई निर्धारण। मौजूदा कानून के तहत, ज्यादातर सेकंड स्ट्राइकर अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से स्वतः रिहा कर दिए जाते हैं। इसके विपरीत, थर्ड स्ट्राइकर्स केवल स्टेट बोर्ड आफ पेरोल हियरिंग्स (BPH) की मंजूरी से ही रिहा होते हैं। थर्ड स्ट्राइकर्स द्वारा उन्हें मिली सजा की न्यूनतम अवधि काट चुकने के बाद, एक BPH पैनल उनकी संभावित रिहाई पर विचार करने के लिए पेरोल विचार सुनवाई आयोजित करता है। उदाहरण के लिए, BPH 25 साल की उम्रकैद पाए किसी थर्ड स्ट्राइकर के लिए इस प्रकार की सुनवाई तब करेगा जब वह 25 साल जेल की सजा काट चुका हो। यदि BPH सुनवाई के समय थर्ड स्ट्राइकर को रिहा नहीं करने का फैसला करता है, तो बोर्ड भविष्य में उसके बाद की सुनवाई आयोजित करेगा। 1994 में तीन हमलों का कानून प्रभावी होने के बाद इस दशक के अंत तक पहले थर्ड स्ट्राइकर्स उनकी जेल से संभावित रिहाई के लिए सुनवाइयों के पात्र होंगे।

रिहाई बाद निगरानी। मौजूदा कानून के तहत सभी सेकंड और थर्ड स्ट्राइकर्स की जेल से रिहाई के बाद समुदाय में निगरानी जरूरी होती है। यदि कोई सेकंड स्ट्राइकर हाल ही किसी अगंभीर, अहिंसक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो समुदाय में उसकी निगरानी काउंटी परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। अन्यथा, सेकंड स्ट्राइकर की समुदाय में निगरानी राज्य पेरोल एजेंट करते हैं। रिहाई के बाद सभी थर्ड स्ट्राइकर्स की निगरानी समुदाय में राज्य

पेरोल एजेंटों द्वारा की जाती है। जब सेकंड अथवा थर्ड स्ट्राइकर्स अपनी सामुदायिक निगरानी की शर्तों का उल्लंघन करते हैं या कोई नया अपराध करते हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार उन्हें काउंटी जेल अथवा राज्य जेल भेजा जाता है।

प्रस्ताव

यह उपाय तीन हमलों के कानून के तहत उन विशेष थर्ड स्ट्राइकर्स द्वारा काटी गई जेल की सजा को कम करता है जिनके मौजूदा अपराध अगंभीर और अहिंसक अपराध हैं। यह उपाय उन कुछ विशेष थर्ड स्ट्राइकर्स को पुनः सजा की अनुमति भी देता है जो विशिष्ट अगंभीर, अहिंसक बड़े अपराधों के लिए मौजूदा समय में उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं। इन दोनों बदलावों का वर्णन नीचे किया गया है।

कुछ थर्ड स्ट्राइकर्स के लिए छोटी सजाएं। इस उपाय के लिए आवश्यक है कि पहले के दो या इससे अधिक गंभीर या हिंसक अपराध में सजायाफ़ता और उसका नया अपराध अगंभीर, अहिंसक हो, उसे नये अपराध के लिए सामान्य अवधि से दोगुनी कैद की सजा हो बजाय मौजूदा तौर पर जरूरी न्यूनतम 25 साल से उम्रकैद की सजा के। उदाहरणस्वरूप, एक थर्ड स्ट्राइकर को जो एक ऐसे अपराध का दोषी हो जिसमें समान्यतया दो से चार साल की सजा होती है, उसे चार से आठ साल कैद की सजा होती है—जो अन्यथा लागू होने वाली अवधि की दोगुनी है—बजाय 25 साल से उम्रकैद के।

हालांकि छोटी सजाओं के कुछ अपवादों के लिए यह उपाय उपलब्ध कराया जाता है। विशेष तौर पर, यह उपाय तब जरूरी होता है यदि दोषी व्यक्ति ने कुछ विशेष नये या पुराने अपराध किए हों, जिनमें कुछ मादक पदार्थ, यौन, और बंदूक संबंधी बड़े अपराध शामिल हैं, वह अभी भी तीन हमलों के कानून के तहत उम्रकैद की सजा का पात्र हो।

कुछ मौजूदा थर्ड स्ट्राइकर्स को दोबारा सजा सुनाना। यह उपाय अदालतों द्वारा विशेष थर्ड स्ट्राइकर्स को दोबारा सजा सुनाने में लागू किये जाने की अनुमति देता है। यह उपाय उन थर्ड स्ट्राइकर्स को दोबारा सजा देने के लिए पात्रता को सीमित करता है जिनका वर्तमान अपराध अगंभीर, अहिंसक है और जिन्होंने विशेष मौजूदा और पहले के अपराधों, जैसेकि कुछ विशेष मादक द्रव्य, यौन,

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

और बंदूक संबंधी बड़े अपराध को अंजाम नहीं दिया है। अदालतें इन दोबारा सजा संबंधी सुनवाईयों को संचालित करते हुए पहले इस बात का निर्धारण करेंगी कि क्या दोषियों का आपराधिक कृत्य इतिहास उन्हें दोबारा सजा सुनाने का पात्र बनाता है। अदालत के लिए पात्र दोषियों को दोबारा सजा सुनाना जरूरी होगा जबतक यह तय नहीं हो जाए कि दोषियों को दोबारा दंडित करना जन सुरक्षा के लिए अनुचित जोखिम भरा होगा। इस बात का निर्धारण करने में कि क्या किसी दोषी से इस प्रकार का खतरा है, अदालत ऐसे किसी भी साक्ष्य पर विचार कर सकती है जो प्रासंगिक हो, जैसे कि दोषी का आपराधिक इतिहास, जेल में उसका व्यवहार, और पुनर्मुधार कार्यक्रम में उसकी भागीदारी। यह उपाय दोबारा सजा प्राप्त दोषियों को उनके हाल फिलहाल के अपराध के लिए पहले दी गयी सजा के बजाय सामान्य अवधि से दोगुनी सजा देने के लिए जरूरी होता है। उन दोषियों, जिनके दोबारा सजा सुनाने के आग्रह को अदालतें अस्वीकार कर चुकी होती हैं, को मूल रूप से सुनाई गई उम्रकैद की सजा जारी रखनी होगी।

वित्तीय प्रभाव

राज्य की जेल संबंधी बचत। यह उपाय राज्य की जेल संबंधी प्रणाली पर कई वित्तीय प्रभाव डालेगा। सबसे महत्वपूर्ण, यह उपाय राज्य जेल के खर्चों को दो तरीके से कम करेगा। पहला, तीन हमलों के कानून के तहत कम कैदी ही उम्रकैद की सजा के लिए जेल में रहेंगे क्योंकि इस उपाय के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के दंड केवल उन थर्ड स्ट्राइकर्स पर लागू होंगे जिनका मौजूदा अपराध गंभीर और हिंसक है। यह कुछ भावी बड़े अपराध के दोषियों की सजाएं कम कर देगा। इस उपाय के राज्य और स्थानीय सरकारों पर अनेकों वित्तीय प्रभाव होंगे। दूसरा, थर्ड स्ट्राइकर्स को दोबारा सजा दिये जाने के परिणामस्वरूप कई मौजूदा कैदी छोटी अवधि की जेल की सजा प्राप्त कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि अगले सत्र की शुरुआत में कैदियों की संख्या घट जाएगी।

यह उपाय राज्य का पेट्रोल खर्च भी घटाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस उपाय से प्रभावित दोषी जेल से रिहा होने के बाद—

जायी

राज्य पेट्रोल की बजाय—सामान्यतया काउंटी परिवीक्षा विभाग की निगरानी में रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मौजूदा अपराध गंभीर और अहिंसक होगा। इसके अतिरिक्त, थर्ड स्ट्राइकर की संख्या में कमी भविष्य में BPH द्वारा पेट्रोल विचार सुनवाईयों को कम कर देगी।

उपरोक्त बदलावों से राज्य की जेल संबंधी बचत लगभग \$70 मिलियन सालाना होने की संभावना है जो अगले दो दशक में और ज्यादा बचत होने से बढ़कर—\$90 मिलियन सालाना तक—हो जाएगी। हालांकि ये सालाना बचतें दसियों मिलियन डॉलर सालाना अधिक या कम हो सकती हैं जो कि कई कारकों पर निर्भर करता है। खासतौर पर, बचतों का वास्तविक स्तर अदालतों द्वारा दोबारा सजा सुनाये गए थर्ड स्ट्राइकर्स की संख्या और उस दर पर निर्भर करेगा जिसपर BPH ने भविष्य में मौजूदा कानून के तहत थर्ड स्ट्राइकर्स को रिहा किया होगा।

दोबारा सजा देने संबंधी खर्चें। इस उपाय के परिणामस्वरूप उन राज्य और काउंटियों पर एक बार का खर्च आएगा जो इस उपाय के दोबारा सजा देने के प्रावधानों से संबंधित हैं। इन प्रावधानों से अदालत में मामले बढ़ेंगे, जिससे जिला अधिवक्ताओं, लोक अभियोजकों, और काउंटी शेरिफ के उन विभागों पर अतिरिक्त खर्चें बढ़ेंगे जो इन दोबारा सजा देने की कार्यवाहियों के वर्कलोड और कर्मचारियों का प्रबंधन करेंगे। इसके अलावा, काउंटियों को दोबारा सजा देने की कार्यवाहियों के दौरान जेल में बंद कैदियों का जेल खर्च उठाना पड़ेगा। दो साल बाद ये खर्च राज्यवार कुछ मिलियन डॉलर हो सकते हैं।

अन्य राजकोषीय प्रभाव। राज्य और काउंटियों के लिए अदालत, परिवीक्षा, और जेल संबंधी कुछ अतिरिक्त खर्चें होंगे। यह इसलिए क्योंकि इस उपाय के कारण जेल से रिहा होने वाले कुछ दोषियों की निगरानी राज्य पेट्रोल की बजाय परिवीक्षा विभागों द्वारा की जाएगी, और अगर वे अपनी निगरानी की शर्तों का उल्लंघन करते हैं या नया अपराध करते हैं तो अदालत की सुनवाई के बाद उन्हें जेल की सजा होगी। हमारा अनुमान है कि इस लंबी अवधि के खर्चें कुछ खास नहीं होंगे।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जायी

यह उपाय अन्य राज्य और स्थानीय सरकार के राजकोषीय प्रभाव पर विभिन्न असर डाल सकता है। उदाहरणस्वरूप, सरकारें काफी हद तक अतिरिक्त खर्च उठाएंगी क्योंकि इस उपाय के कारण जेल से रिहा होने वाले अपराधियों को सरकारी सेवाओं की जरूरत होती है (जैसेकि निजी बीमा नहीं कराने वाले लोगों के लिए सरकारी

स्वास्थ्य सुरक्षा) या उन्होंने अतिरिक्त अपराध को अंजाम दिया हो। राज्य और स्थानीय सरकार को एक हद तक अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी हो सकती है क्योंकि इस उपाय के कारण जेल से रिहा होने वाले अपराधी कार्यबल में शामिल हो जाते हैं। इन प्रभावों की महत्ता अज्ञात है।